

संवधान की नौवीं अनुसूची

प्रलिस के लयः

आरक्षण, संवधान (पहला संशोधन) अधनलय, 1951 ।

मेन्स के लयः

संवधान की नौवीं अनुसूची ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लखकर [संवधान की नौवीं अनुसूची](#) में नौकरयों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उच्च कोटे की अनुमतल देने वाले दो संशोधन वधलयकों को शामिल करने की मांग की ।

क्या है वधलयक?

- छत्तीसगढ़ में राज्य वधानसभा ने सर्वसम्मतल से [अनुसूचित जातल, अनुसूचित जनजातल](#) और [अन्य पछिड़ा वर्ग](#) के सदस्यो के लयल 76% कोटा हेतु दो संशोधन वधलयको को मंजूरी दे दी है ।
- [राज्यपाल](#) ने अभी तक इन वधलयको को मंजूरी नहीं दी है ।

वधलयको को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता:

- संवधान की नौवीं अनुसूची में [केंद्रीय और राज्य कानूनो की एक सूची](#) शामिल है जन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है । नौवीं अनुसूची में दो संशोधन वधलयको को शामिल करने से वे कानूनी चुनौतयों से मुक्त हो जाएंगे ।
- छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है क नौवीं अनुसूची में संशोधतल प्रावधानों को शामिल करनाराज्य में [पछिड़े और वंचतल वर्गो को न्याय दलाने के लयल महत्त्वपूर्ण है](#) ।
- इससे पहले [छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय](#) ने 58% कोटा की अनुमतल देने वाले एक सरकारी आदेश को रद्द कर दयल था, जसमें कहा गया था क [आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता](#) क्योकल यह असंवधानकल है ।
 - हालांकल [अनुसूचित जातल, अनुसूचित जनजातल](#) और [अन्य पछिड़े वर्गो को 76% आरक्षण प्रदान करने के लयल राज्य वधानसभा द्वारा दो संशोधन वधलयक पारतल कयल गए थे](#) ।

नौवीं अनुसूची:

- इस अनुसूची में [केंद्रीय और राज्य कानूनो की एक सूची](#) है जसल न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है जसल [संवधान \(प्रथम संशोधन\) अधनलय, 1951](#) द्वारा जोड़ा गया था ।
 - पहले संशोधन में [अनुसूची में 13 कानूनो को जोड़ा](#) गया था । बाद के वभलनल संशोधनो सहतल वर्तमान में संरक्षण कानूनो की संख्या 284 हो गई है ।
- यह नए अनुच्छेद 31B के तहत बनाया गया था, जसल अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा [कृषल सुधार से संबंधतल कानूनो की रक्षा करने और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था](#) ।
 - अनुच्छेद 31A कानून के 'उपबंधो' को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकल अनुच्छेद 31B वशिषटकानूनो या अधनलयो को सुरक्षा प्रदान करता है ।
 - जबकल अनुसूची के तहत संरक्षणतल अधकलश कानून कृषल/भूमल के मुद्दो से संबंधतल हैं, सूची में अन्य वषय भी शामिल हैं ।
- अनुच्छेद 31B में एक पूर्ववयापी संचालन भी है, जसलका अर्थ है कल यदल कानूनो को असंवधानकल घोषतल कयल जाने के बाकौवीं अनुसूची में शामिल कयल जाता है, तो उन्हें उनकी स्थापना के बाद से अनुसूची में माना जाता है, अतः उन्हें वैध माना जाता है ।
- इस तथ्य के बावजूद कल अनुच्छेद 31B न्यायकल समीक्षा के बाहर है, [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पहले कहा है कल नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून

भी समीक्षा के अधीन होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या [संवंधान के मौलिक सिद्धांतों](#) का उल्लंघन करते हैं।

क्या नौवीं अनुसूची के कानून न्यायिक जाँच से पूरी तरह मुक्त हैं?

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में नरिणय को बरकरार रखा तथा "भारतीय संवंधान की मूल संरचना" की एक नई अवधारणा पेश की और कहा कि, "संवंधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन यह उन संशोधनों को संवंधान के बुनियादी ढाँचे से हटा देगा जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, न्यायालय द्वारा खारजि किये जाने के योग्य हैं"।
- **वामन राव बनाम भारत संघ (1981):** इस महत्त्वपूर्ण नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 (जिस पर केशवानंद भारती मामले में नरिणय दिया गया था) से पहले संवंधान में किये गए थे, वैध और संवंधानिक हैं लेकिन जो नरिदष्टि तथिक के बाद बनाए गए थे, उन्हें संवंधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- **आई आर कोल्हो बनाम तमलिनाडु राज्य (2007):** यह माना गया था कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू होने पर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हर कानून का परीक्षण किया जाना चाहिये।
 - इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अपने पछिले नरिणयों को बरकरार रखा और घोषित किया कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है तथा यदि यह संवंधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है तो न्यायापालिका द्वारा जाँच के लिये खुला है।
 - इसके अलावा यह भी कहा गया कि यदि नौवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवंधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फरि से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. भारत की संसद किसी कानून वशिष को भारत के संवंधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून वशिष की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और उस पर कोई नरिणय भी नहीं दिया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. नौवीं अनुसूची को भारत के संवंधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? (2019)

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) लाल बहादुर शास्त्री
- (c) इंदिरा गांधी
- (d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

प्रश्न:

प्रश्न. कोहलियो केस में क्या अभनिरिधारति किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन संवंधान के बुनियादी अभलिकषणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

स्रोत: द हद्रि

